आज दिनांक 22.09.2014 को संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के अध्यक्षता में विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

उपस्थितिः— पंजी में संधारित।

कार्यवाहीः—

कृषि योजनाओं की स्वीकृत एवं व्यय की समीक्षा की गई, जो निम्न स्थिति पाई गई।

1. कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध मे श्री अनील कुमार झा, सिंचाई विशेषज्ञ ने बताया कि किशनगंज कॉलेज की स्वीकृत्यादेश में कुछ सूचनाएँ जोड़ना है तथा नूरसराय उद्यान कॉलेज नालंदा में फर्नीचर क्रय करना है, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में बजट नहीं रहने के कारण लम्बित है। किसान आयोग की योजना स्वीकृत हो गई है तथा आवंटन भी दे दिया गया है।
2. निदेशक, बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक 25.09.2014 को आयोजित G.B. की बैठक में गत वर्ष का 1.15 करोड़ अवशेष राशि व्यय के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।
3. उद्यान से सम्बन्धित स्वीकृत योजना के सम्बन्ध में बजट पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वीकृत्यादेश में किस बजट शीर्ष के अधीन कितनी राशि की निकासी होनी है, का उल्लेख नहीं है। इससे आवंटन निर्गत करने में कठिनाई हो रही है। उप कृषि निदेशक (उद्यान) को निदेश दिया गया कि स्वीकृत्यादेश में सुधार करा लें। पहले यह कार्य पी0 पी0 एम0 कोषांग से होता था परन्तु जब से यह कार्य नोडल पदाधिकारी करने लगे तो अब उसी संचिका से शुद्धि पत्र भी निर्गत होगा।
4. बीजगुणन प्रक्षेत्रों एवं अनुदान बीज वितरण योजना के सम्ब्न्ध में जानकारी दी गई कि स्वीकृत्यादेश के प्रारूप में अंकित राशि में भिन्नता है, उप कृषि निदेशक (बीज) को निदेश दिया गया कि उसमें सुधार कर प्रस्तुत किंया जाय।
5. कृषि यांत्रिकरण के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 26.09.2014 से जिलों में यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन हो रहा है। स्वीकृत्यादेश हो गया है वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में स्वीकृत्यादेश की कंडिकाओं में परिवर्त्तन करना है, क्योंकि अब राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा होना है। निदेश दिया गया कि राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण सेल को स्वीकृत्यादेश में संशोधन की आवश्यक कार्रवाई कर समक्ष प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करा लिया जाय।
6. बजट पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे भाड़े पर वाहन में आवंटन देने के लिये एक निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बंधित पदाधिकारी से पुनः मांग पत्र भेज कर पत्र प्राप्त करेगें।
7. ई—किसान भवन के संबंध में संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान) द्वारा बताया गया कि 210 ई—किसान भवन निर्माण में 60 ई—किसान भवन जो नवसृजित प्रखंड है, में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है।
8. टाल दियारा योजना के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि योजना की स्वीकृति हो गई है। दियारा विकास की योजना स्थायी वित्त समिति के बैठक कराकर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

C:\Users\Dell\Desktop\Shreewastav\Proceeding 22-09-2014.docx